RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 14 DECEMBER TO 20 DECEMBER 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 13 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

नवंबर में थोक मुद्रास्फीति घटकर 5.85 प्रतिशत पर, 21 माह का निचला स्तर Page 2

अपराध की श्रेणी से बाहर होंगी जीएसटी से जुड़ी गड़बड़ियां? 17 दिसंबर को होगी बैठक Page 3

एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान सात फीसदी पर अपरिवर्तित रखा Page 4

editoria!

रुपये में व्यापार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर, पाउंड, येन, यूरो जैसी कुछ मुद्राओं का वर्चस्व है. इस कारण अन्य मुद्राओं को इनकी कीमतों के अनुसार संचालित होना पड़ता है. कुछ मुद्राओं की विशिष्टता के उनके देशों का महत्व भी बहुत अधिक होता है तथा वे अपने हितों के अनुरूप कार्य करते हैं. भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है तथा हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में रुपये को विनिमय के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित करना आवश्यक है. भारत सरकार और रिजर्व बैंक अनेक देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श कर रहे हैं तथा इसमें प्रगति भी हो रही है. कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने रुपये में भुगतान के लिए विशेष व्यवस्था करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इस क्रम में उल्लेखनीय पहल करते हुए सरकार ने व्यापारिक संगठनों और बैंकों से कहा है कि वे दूसरे देशों के साथ संबंधित संभावनाओं की तलाश करें. रुपये में व्यापार की वर्तमान व्यवस्था रूस, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ कार्यरत है. इसके अनुभवों का लाभ उठाया जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा के अनुरूप विशेष रूप से वोस्ट्रो खाते खोलने होते हैं. व्यापारियों का भुगतान इन्हीं खातों से होता है. अब तक ऐसे 18 विशेष रुपये खाते खोले जा चुके हैं तथा इस प्रक्रिया में 11 बैंक भागीदार हैं. इन खातों के अलावा भारत के लेन-देन के स्थानीय तरीकों को भी अंतरराष्ट्रीय बनाने का आग्रह सरकार की ओर से किया गया है. कुछ मुद्राओं का वर्चस्व भू-राजनीतिक हितों के लिए भी जोखिम साबित हो सकता है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर जो आर्थिक पाबंदियां लगायी हैं, उनमें यह प्रावधान भी है कि रूसी मुद्रा रूबल में वे कारोबार नहीं करेंगे. यह मसला भी वैश्विक वित्त बाजार में उठाया जाता रहा है कि मजबूत मुद्राओं वाले देश उनकी कीमतों को अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए घटाते-बढ़ाते रहते हैं. ऐसे रवैये से भारतीय मुद्रा भी प्रभावित होती है. यदि मुद्रा की कीमत घटती है, तो निवेश पर भी प्रतिकूल असर होता है तथा बाहर की देनदारियां भी महंगी हो जाती हैं. भारत का द्विपक्षीय व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है. सरकार विभिन्न देशों के साथ या तो मुक्त व्यापार संधियां कर चुकी है या उनके संबंध में बातचीत चल रही है. जब दो देशों के बीच खरीद-बिक्री हो रही है, तो फिर किसी अन्य असंबद्ध मुद्रा में लेन-देन का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है. वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने तथा रुपये को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मानचित्र पर स्थापित करने में इस पहल से बड़ी मदद मिलेगी. इस प्रयास में कारोबारियों और बैंकों को अहम भूमिका निभानी है.

8 साल में सबसे सस्ता कच्चा तेल, क्या 35 रुपये कम हो जाएंगे पेट्रोल के दाम? समझें गणित

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर देश को रूसी ऑयल 49 डॉलर पर मिलना शुरू हो जाता है तो देश में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये से 35 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की चर्चा है। खासकर रूसी क्रूड ऑयल की, जिस पर जी 7, यूरोप और सहयोगी देशों ने 60 डॉलर की कैपिंग कर दी है। इसका मतलब है कि रूस अब 60 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पर क्रूड ऑयल नहीं बेच सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत को रूसी ऑयल जी 7 की कैपिंग से भी 11 डॉलर सस्ता मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत 8 सालों में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल खरीदेगा। जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में 30 से 35 रुपये गिरावट आ सकती है। आइए बताते हैं कि आखिर तेल के इस खेल में भारत को कैसे और किस तरह से फायदा हो सकता है।

तो 61 रुपये पर आ जाएगा पेट्रोल

अगर देश को क्रूड ऑयल 2015 की कीमतों

में मिलना शुरू होगा तो अब सवाल यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी उसी दौर के समान हो जाएंगी? इस मामले में आईआईएफएल के वाइस प्रेसीडेंट अनुज गुप्ता ने कहा कि अगर देश को रूसी ऑयल 49 डॉलर पर मिलना शुरू हो जाता है तो देश में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये से 35 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि देश पेट्रोल के दाम 61 रुपये पर आ जाएंगे। वहीं डीजल की कीमत में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है. डीजल के दाम 40 रुपये से ज्यादा कम हो सकते हैं। इस मतलब है कि डीजल के दाम 50 रुपये से नीचे जा सकते हैं। नवंबर के महीने जब ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 49 डॉलर प्रति बैरल पर थे। जबकि देश में उस समय प्रत्येक 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव देखने को मिलता था। देश की राजधानी दिल्ली में 2 नवंबर को पेट्रोल के दाम 61.06 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 46.80 रुपये प्रति लीटर पर थे। इसका मतलब साफ है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भी 2015 के लेवल पर आ सकते हैं।

Budget 2023:

गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी घटाने की जरूरत, बढ़ेगी सोने की चमक

नई दिल्ली। एजेंसी

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 1 फरवरी 2023 को पेश करेंगी। इससे पहले वह इंडस्ट्री के सभी सेक्टर से जुड़े लोगों की राय जानने की कोशिश कर रही हैं। बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने भी वित्त मंत्री को बजट से अपनी उम्मीदों के बारे में बताया है। गोल्ड की खपत में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गोल्ड की स्मगलिंग रोकने के लिए कस्टम ड्यूटी 4% करने का ऐलान बजट में होना चाहिए। साथ ही जीएसटी में कमी लाना भी जरूरी है। बुलियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बजट में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1. कस्टम ड्यूटी अभी 12.5% है। इस पर 2.5% सेस लगता है। इससे कुल ड्यूटी 15% पहुंच जाती है। अगर कस्टम ड्यूटी को घटाया जाता है तो देश में स्मगलिंग को रोकने में मदद मिलेगी। अभी इस ड्यूटी से बचने के लिए गोल्ड की स्मगलिंग की जाती है।

2. सभी प्रकार के व्यापारियों पर इनकम टैक्स के निम्नलिखित स्लैब लागू करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इससे व्यापारी वर्ग को काफी राहत मिलेगी। 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 5₹, 50 लाख तक 10₹, 1 करोड़ रुपये तक 15% और 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पर 20% टैक्स लगाया जाना चाहिए।

3. गोल्ड पर जीएसटी की दर 1% किया जाना चाहिये। अभी यह दर अधिकतम 3 फीसदी है। इसके कारण कई बार ग्राहक पक्का बिल नहीं बनवाना चाहते हैं। अगर टैक्स कम 1 फीसदी होगा तो ग्राहकों को टैक्स देने में परेशानी नहीं होगी। अभी अगर ग्राहक 10 लाख रुपये की ज्वैलरी खरीदता है तो 3 फीसदी के हिसाब से उसे 30,000 रुपये देने होते हैं। इसलिए ग्राहक टैक्स देने में आनाकानी करता है। टैक्स 1 फीसदी होगा तो यह 10,000 रुपये बनेगा। इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ग्राहक टैक्स चुकाना चाहेंगे।

4. सेलर्स के जीएसटी नहीं जमा कराने पर बायर का टैक्स क्रेडिट नहीं रोकने पर विचार किया जाना चाहिये।

5. इनकम टैक्स या जीएसटी की बकाया देनदारी पर अधिकतम 6% तक ब्याज वसूले जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

6. लेट फीस के नाम पर अधिकतम 100 रुपये जुर्माना वसूले जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

7. खरीद पर टीडीएस व बिक्री पर टीसीएस दोनों में से एक को तुरंत हटाने पर विचार करना चाहिये।

8. स्टॉक वैल्यूएशन पर लीफो सिस्टम लागू किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

पेपरवर्क का बोझ घटाने से होगा इंडस्ट्री को फायदा

व्यापारी का ज्यादातर समय कागजी कार्यवाही में खराब होता है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है। वित्तमंत्री को आयात शुल्क के अलावा सभी प्रकार के टैक्स हटाकर केवल आधा (1/2%) परसेंट बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लगाने पर जल्द विचार करना चाहिये. इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिये ज्यादा समय मिल सकेगा।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया चार पैसे टूटकर 82.64 पर आया

मुंबई। एजेंसी

विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और निवेशकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे की गिरावट के साथ 82.64 के स्तर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में तेजी से घरेलू मुद्रा को मजबूती मिली। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.60 पर खुला, फिर और गिरावट के साथ 82.64 के स्तर पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले चार पैसे की गिरावट को दर्शाता है। शुरुआती सौदों में रुपया 82.60-82.65 के सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटकर 82.60 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 104.09 पर आ गया। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 80.41 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गया।

News यू केन USE

मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरतः सीतारमण

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने और समय पर अभियोजन सुनिश्चित करने को लेकर सीमा शुल्क अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा। सीतारमण ने कहा, ''अगर सोने की तस्करी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, मादक पदार्थ पीढ़ियों को प्रभावित करता है। हमें मादक पदार्थों की जब्ती और समयबद्ध अभियोजन को लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरत है। हमें हर मामले को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचाने की जरूरत है।'' उन्होंने सीमा शुल्क कानून के 60 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से नियमों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन को लेकर अगले 25 साल की योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने ऐसे विचार भी देने को कहा, जिनका दुनिया अनुकरण कर सके। सीतारमण ने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क विभाग को डार्क नेट, कृत्रिम मेधा, वेब3 और मेटावर्स जैसे प्रौद्योगिकी को उपयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों को प्राप्त खुफिया सूचनाओं का उपयोग करने में भी अधिकतम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रवर्तन एजेंसियों ने चालू वर्ष में 30 नवंबर तक 3,017 किलोग्राम हेरोइन और 122 किलो कोकीन जब्त की है।

जी20 देशों को भारत का निर्यात 2030 तक 500 अरब डॉलर होगाः पीएचडीसीसीआई

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत का वर्ष 2030 तक जी20 देशों को वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है जिससे उसके व्यापार घाटे में खासी गिरावट आ सकती है। उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने मंगलवार को यह उम्मीद जताई। पीएचडी चैंबर के अध्यक्ष साकेत डालमिया ने कहा कि जी20 देशों में से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत अनिश्चितताओं को अवसरों में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डालमिया ने कहा, ''जी20 की अध्यक्षता का भारत के पास आना भू-राजनीतिक तनाव, उच्च मुद्रास्फीति और सुस्त होती आर्थिक वृद्धि के दौर में स्थिरता लाने के लिहाज से असरदार साबित होगा।'' उन्होंने कहा कि जी20 देशों के साथ निर्यात बढ़ने की प्रचुर संभावना है और भारत का वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 में यह 212 अरब डॉलर रहा था। डालमिया ने कहा कि जी20 देशों के साथ कारोबारी गतिविधियों का विस्तार होने से भारत का इन देशों के साथ व्यापार घाटा 50 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिलेगी। अभी जी20 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 107 अरब डॉलर है।

तुर्की ने रोका भारत का तेल, कच्चा तेल लेकर आ रहे कई देशों के जहाज फंसे, जानिए वजह

कई देशों के मालवाहक जहाज तुर्की की जल सीमा में फंस गए हैं। तुर्की के अधिकारियों ने अमेरिका के दबाव में अडंगा लाग दिया है। पहले तुर्की के अधिकारियों ने मालजहाजों पर कई नियम शर्तों थोप दिया है। जिसमें मालवाहक जहाजों को यह दिखाना होगा कि तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से कम में खरीदा गया है। कई देशों के मालवाहक जहाज तुर्की की जल सीमा में फंस गए हैं। तुर्की के अधिकारियों ने अमेरिका के दबाव में अडंगा लाग दिया है। पहले तुर्की के अधिकारियों ने मालजहाजों पर कई नियम शर्तों थोप दिया है। जिसमें मालवाहक जहाजों को यह दिखाना

होगा कि तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से कम में खरीदा गया है।

दरअसल, G-7 देशों ने रूस के क्रूड पर 60 डॉलर प्रति बैरल का कैप लगा दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि रूस का तेल इससे ज्यादा महंगा नहीं होगा। भारत तेल लेकर आ रहे टैंकर में 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा है। तुर्की के इस नए फरमान से 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल लदे कम से कम 20 मालवाहक जहाज कई दिनों से खड़े हैं। ये सभी मालवाहक जहाज बोस्फोरस और डार्डानेल्स शिपिंग जलडमरूमध्य से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की अधिकारी पहले बीमा के पेपर वेबसाइट देखकर इजाजत दे देते थे। लेकिन, अमेरिका और इंग्लैंड के दबाव में तुर्की ने ऐसा जानिए तुर्की ने क्यों फंसाया पेंच रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ऐसे में अमेरिकी की अगुवाई में कई देश रूस पर प्राइस कैप लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि रूस महंगे दाम पर कच्चा तेल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा है। उस पैसे को यूक्रेन से हो रहे युद्ध में लगा रहा है। ऐसे में जी-7 देशों ने प्राइस कैप लगा दिया। तुर्की नाटो में शामिल है। ऐसे में रूस से कच्चा तेल लेकर निकलने वाले मालवाहक जहाजों पर पेंच फंसा रहा है।

नवंबर में थोक मुद्रास्फीति घटकर 5.85 प्रतिशत पर, 21 माह का निचला स्तर

नयी दिल्ली। एजेंसी

विनिर्मित उत्पादों, ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 21 महीने के निचले स्तर 5.85 प्रतिशत पर आ गई है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति में मई से गिरावट आ रही है। अक्टूबर में यह घटकर एक अंक में यानी 8.39 प्रतिशत पर आ गई थी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा, ''नवंबर, 2022 में मुद्रास्फीति की दर में कमी आने की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, मूल धातुओं, कपड़ा, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, कागज एवं इससे बने उत्पादों के दामों में गिरावट आना है।'' नवंबर, 2022 से पहले मुद्रास्फीति का निचला स्तर फरवरी, 2021 में रहा था। उस समय यह 4.83 प्रतिशत पर थी। इस बारे में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि महंगाई को और कम करने के लिए सरकार आम जनता के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के जवाब में लोकसभा में कहा, ''मुद्रास्फीति प्रबंधन या नियंत्रण...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का समूह एवं अधिकारी समय-समय पर हस्तक्षेप करते हैं और कदम उठा रहे हैं जिसके परिणाम दिखने लगे हैं।''

नवंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 1.07 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले महीने 8.33 प्रतिशत थी। समीक्षाधीन महीने में सब्जियों की मुद्रास्फीति शून्य से नीचे 20.08 फीसदी पर आ गई, जो अक्टूबर में 17.61 प्रतिशत पर थी। खाद्य वस्तुओं में फलों, सब्जियों विशेषकर टमाटर और आलू के दामों में कमी आई है हालांकि गेहूं, दाल और दुग्ध उत्पादों के दाम बढ़े हैं। ईंधन और बिजली की महंगाई दर नवंबर में 17.35 प्रतिशत रही। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति 3.59 प्रतिशत पर थी। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर निर्णय करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति 11 माह में पहली बार, नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक के छह फीसदी के संतोषजनक स्तर से नीचे आई है।

एयर इंडिया 50 बोइंग 737 मैक्स विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब

मुंबई। एजेंसी

टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया अपेक्षाकृत छोटे आकार के 50 बोइंग 737 मैक्स विमान खरीदने के लिये अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। कंपनी ये विमान सस्ती अंतरराष्ट्रीय सेवाएं देने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिये खरीद रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि यह सौदा बड़े विमान के ऑर्डर का हिस्सा होगा। इसको लेकर कंपनी बोइंग और एयरबस एसई के साथ चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से ही बात कर रही है। घाटे में चल रही एयर इंडिया की अगले तीन साल में अपने विमानों के बड़े को तीन गुना करने की योजना है। टाटा समूह ने इस साल जनवरी में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। एयरलाइन कारोबार को सुदृढ़ बनाने के लिये टाटा समूह ने अपनी घरेलू इकाई एयर एशिया इंडिया के एयर इंडिया में विलय की भी घोषणा की है। कंपनी एयरबस ए320 विमानों के बेड़े का परिचालन करती है। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 बोइंग 737 विमानों का बेड़ा है। सूत्रों ने कहा कि सौदे पर आगे की चर्चा के लिये एयर इंडिया और बोइंग के अधिकारियों की सोमवार को बैठक होने की संभावना है। उन्होंने कहा, ''एयर इंडिया ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिये 50 बोइंग 737 मैक्स विमान खरीदने को लेकर बोइंग के साथ सौदे को लगभग अंतिम रूप दे दिया है।'' हालांकि, इस बारे में एयर इंडिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

देश को एक से अधिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरतः गडकरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि देश को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिये एक से अधिक ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों (फ्लेक्स फ्यूल) और ई-वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। 'फ्लेक्स फ्यूल' के लिये उपयुक्त वाहनों में एक से अधिक ईंधन या दो ईंधन के मिश्रण को उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और एथनॉल या मेथनॉल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने वाहन कंपनियों के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि ईंधन की ऊंची लागत से विमानन क्षेत्र भी समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, ''हर साल कच्चे तेल के दाम में काफी उतार-चढ़ाव आता है। इससे समस्याएं पैदा होती हैं...हमें इससे निपटने के लिये पूरी तरह से विभिन्न ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है।'' गडकरी ने कहा कि देश में 40 प्रतिशत प्रदूषण का कारण पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन हैं। उन्होंने कहा, ''हम कई उद्योगों को एथनॉल उत्पादन के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं।'' गडकरी ने कार्यक्रम में कहा, ''प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मैं आप सभी के लिये महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय ने जो सड़कें विकसित की हैं, उससे सबसे ज्यादा उद्योग को ही लाभ होगा।'' उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय 27 नये एक्सप्रेसवे बना रहा है और उन्हें 'रोपवे' तथा 'फ्यूनीक्यूलर रेलवे' (केबल रेल) प्रणाली की 260 परियोजनाएं मिली हैं।

अपराध की श्रेणी से बाहर होंगी जीएसटी से जुड़ी गड़बड़ियां? 17 दिसंबर को होगी बैठक

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से अलग करने और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन पर निर्णय किये जाने की संभावना है. परिषद की बैठक 17 दिसंबर को होनी है।

जीएसटी परिषद की बैठक में क्या होगा?

सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद की विधि समिति ने रिपोर्ट में जीएसटी के तहत अपराधों के लिये अभियोजन चलाने को लेकर मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है। समिति में केंद्र और राज्यों के विधि अधिकारी शामिल हैं। विधि समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि कारोबार सुगमता के लिये जीएसटी में अपराधों के निपटान को लेकर जुर्माने की राशि को कम किया जाए। इसके अलावा, परिषद 'ऑनलाइन गेमिंग', कसीनो और घुड़दौड़ पर कराधान से संबंधित मुद्दों पर विचार कर सकती है। परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) को 'ऑनलाइन गेमिंग', कसीनो और घुड़दौड़ पर कर की दर के बारे में निर्णय करना है।

वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगा परिषद

समूह ने पिछले महीने इस बारे में विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली. ऐसा समझा जाता है कि जीओएम ने 'ऑनलाइन गेमिंग', कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। भले ही वह कौशल पर आधारित खेल हो या फिर किस्मत आधारित। हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं है कि पोर्टल द्वारा वसूले जाने पर शुल्क पर कर लगाया जाए या फिर प्रतिभागियों से दांव लगाने को लेकर प्राप्त राशि पर. हालांकि, जीओएम ने अभी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री को नहीं दी है। समूह परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक से पहले अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप सकता है।

न्यायाधिकरण के गठन पर भी विचार

जीएसटी में गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने के संदर्भ में विधि समिति ने अभियोजन चलाने की सीमा मौजूदा पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है. सूत्रों के अनुसार, परिषद की 17 दिसंबर को 'ऑनलाइन' होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन पर भी विचार किया जा सकता है। जीओएम ने सुझाव दिया है कि न्यायाधिकरणों में दो न्यायिक सदस्य और केंद्र तथा राज्यों एक-एक तकनीकी सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे।

कम हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस की जीएसटी, ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो के दरें बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली। एजेंसी

हेल्थ इंश्योरेंस लेना सस्ता हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18 फीसद से कम करके 12 फीसद किया जा सकता है। आगामी 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों ने जीएसटी काउंसिल से हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी की दरों को कम करने की गुजारिश की है। सरकार भी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे को बढ़ाना चाहती है और 2047 तक देश के सभी नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस के अधीन लाने का प्रयास है। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक, 18 फीसद की जगह 12 फीसद जीएसटी करने से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो जाएगा और इस कारण और अधिक ग्राहक आकर्षित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर जीएसटी की दरों को बढ़ाकर 28 फीसद किया जा सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग पर अभी 18 फीसद जीएसटी लगता है। काउंसिल की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग व कैसिनो पर जीएसटी दरों की समीक्षा और निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया गया था। जीएसटी काउंसिल की गत बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग व कैसिनो पर जीएसटी निर्धारण के मामले में कई मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं हो पाई थी, इसलिए कोई फैसला नहीं हो पाया था।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी चोरी के कई मामले सामने आए हैं जिनकी जांच चल रही है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में बताया था कि वर्ष 2019 के अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 की अवधि में गेमिंग कंपनियों से जुड़े 23,000 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले सामने आए हैं और कर अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं। आगामी 17 दिसंबर को काउंसिल की बैठक में जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तारी के प्रविधान में भी बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, अभी एक करोड़ से अधिक की कर चोरी के मामले में जेल का प्रविधान है और इस सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ किया जा सकता है। काउंसिल की बैठक में जीएसटी अपिलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना को भी हरी झंडी मिल सकती है।

सरकार ने रेलवे स्टेशनों के मौद्रीकरण के लिए पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव वापस लिया

नयी दिल्ली। एजेंसी

रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये रेलवे स्टेशनों का मौद्रीकरण करने का प्रस्ताव वापस ले लिया है और अब इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) माध्यम से किया जा रहा है। एक सूत्र ने जानकारी देते हुए कहा, "बड़ी परिसंपत्ति वाली श्रेणी (स्टेशनों) के बारे में प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। पीपीपी मॉडल पर इन स्टेशनों के मौद्रीकरण के लिए लाए गए प्रस्ताव की जगह अब इन परियोजनाओं को ईपीसी मॉडल पर क्रियान्वित किया जा रहा है।"

ईपीसी मॉडल में इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण गतिविधियां संचालित की जाती हैं। अब रेलवे स्टेशनों के लिए यही मॉडल अपनाया जा रहा है।

सूत्र ने कहा कि रेल मंत्रालय को अब ट्रेनों, मालगोदाम, पर्वतीय रेल, स्टेडियम, रेलवे कॉलोनी एवं रेलवे के पास मौजूद जमीन के मौद्रीकरण में तेजी लाने को कहा गया है। दरअसल राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत रेलवे चालू वित्त वर्ष में अभी तक सिर्फ 1,829 करोड़ रुपये ही जुटा पाया है जबकि लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये रखा गया था। सूत्र ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रेल परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से 4,999 करोड़ रुपये ही जुट पाने का अनुमान है।

रेलवे स्टेशनों का पीपीपी मॉडल से मौद्रीकरण किए जाने का प्रस्ताव वापस लिए जाने के बारे में टिप्पणी के लिए रेल मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 14 नवंबर को नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) परमेश्वरन अय्यर के साथ एक बैठक में एनएमपी योजना की प्रगति का जायजा लिया था। सीतारमण ने अगस्त, 2021 में विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की एनएमपी योजना पेश की थी। इस बारे में नीति आयोग ने ढांचागत क्षेत्रों वाले मंत्रालयों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट भी बनाई थी।

News यू केन USE

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया चार पैसे टूटकर 82.64 पर आया

मुंबई। एजेंसी

विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और निवेशकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे की गिरावट के साथ 82.64 के स्तर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में तेजी से घरेलू मुद्रा को मजबूती मिली। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.60 पर खुला, फिर और गिरावट के साथ 82.64 के स्तर पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले चार पैसे की गिरावट को दर्शाता है।

शुरुआती सौदों में रुपया 82.60-82.65 के सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटकर 82.60 पर बंद हुआ था। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 104.09 पर आ गया। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 80.41 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गया।

इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण, विकास पर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी महिंद्रा

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) लिमिटेड अगले सात-आठ साल में महाराष्ट्र के पुणे में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण और विकास पर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एमएंडएम ने बुधवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि महाराष्ट्र सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत ईवी खंड के लिए 10,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है कि कंपनी अपनी अनुषंगी इकाई के जरिये विनिर्माण सुविधा, महिंद्रा के आगामी बॉर्न इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) के विकास और उत्पादन पर अगले सात-आठ साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इनमें से कुछ बीईवी को 15 अगस्त, 2022 को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में प्रदर्शित किया गया था। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी इन्लो ईवी मंच पर आधारित है। इसे एक्सयूवी ब्रांड और बिल्कुल नए सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्रांड 'बीई' के तहत पेश किया जाएगा।

ब्रिटेन में मुद्रास्फीति नरम होकर नवंबर में 10.7 प्रतिशत पर

लंदन। एजेंसी

ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की गति धीमी पड़ने के साथ महंगाई दर नवंबर में नरम हुई है। हालांकि, यह अब भी 40 साल के उच्चस्तर के करीब है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर नवंबर में सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत रही। यह अक्टूबर में 41 साल के उच्चस्तर 11.1 प्रतिशत प्रतिशत थी। नवंबर महीने की महंगाई दर अर्थशास्त्रियों के जताये गये 10.9 प्रतिशत के अनुमान से कम है। इससे पहले, अमेरिका में भी मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने हल्की नरमी आई है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर नवंबर में घटकर 7.1 प्रतिशत पर आ गयी जो अक्टूबर में 7.7 प्रतिशत थी। हालांकि, ब्रिटेन के अधिकारियों के अनुसार अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच चुकी है। ठंड पड़ने के साथ बिजली और गैस के दाम में तेजी से महंगाई पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

एसयूवी और यूपीआई पर जीएसटी देनदारी स्पष्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

कई चीजों पर कर की दुविधा दूर करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (उएऊ) परिषद की फिटमेंट समिति ने स्पष्ट किया कि निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) पर 22 फीसदी मुआवजा उपकर लगाया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के राजस्व अधिकारियों वाली इस समिति ने आगे स्पष्ट किया कि रुपे/भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को मिलने वाले भुगतान पर कर नहीं लगेगा। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि सदस्य बैंकों को दिया गया प्रोत्साहन और कुछ नहीं बल्कि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी है।

इन मुद्दों पर समिति के स्पष्टीकरण पर जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जाएगा। परिषद की बैठक 17 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी।

एसयूवी के मामले में उद्योग ने एंट्री और विवरण में अस्पष्टता का हवाला देते हुए ऐसे वाहनों की आपूर्ति पर लागू जीएसटी मुआवजा उपकर की दर पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। समिति ने कहा, 'जीएसटी व्यवस्था में मुआवजा उपकर के लिए वर्तमान एंट्री पहले की केंद्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था में एंट्री के समान है। लेकिन एसयूवी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और विवरण में केवल एक स्पष्टीकरण दिया गया है।'

विभिन्न प्रकार के वाहनों पर जीएसटी की दर अलग-अलग है। वाहनों पर 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। मगर वाहनों की बिक्री पर जीएसटी के साथ मुआवजा उपकर भी लगता है, जो 22 फीसदी तक हो सकता है। समिति ने कहा कि परिषद की सिफारिशें सभी चार शर्तों को पूरा करने वाले वाहनों पर

उच्च दर से उपकर लगाने के बारे में थीं। इन शर्तों में इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक होना, लंबाई 4000 मिली मीटर से अधिक और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिलीमीटर होना शामिल है। मगर एक और स्पष्टीकरण जारी कर स्पष्ट किया जा सकता है कि 22 फीसदी की उच्च मुआवजा उपकर दर लगाने के लिए वाहन को इन सभी चार शर्तों को पूरा करने की जरूरत होगी।

बैंकों को मिलने वाले प्रोत्साहन के बारे में फिटमेंट समिति ने स्पष्ट किया कि संबंधित प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को उनकी सेवा के लिए किया गया भुगतान नहीं है बल्कि प्रोत्साहन है क्योंकि यह बैंकों द्वारा लेनदेन की संख्या के आधार पर न्यूनतम वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। जीएसटी पर फिटमेंट समिति ने कहा, 'सरकार उन्हें रुपे/भीम-यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक केंद्र सरकार को कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं।' यह भी कहा गया कि बैंकों को दिया जाने वाला यह प्रोत्साहन उसी तरह है जैसे निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें निर्यातक सरकार के लिए निर्यात नहीं करते हैं, लेकिन देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा समिति ने व्यापक अध्ययन की आवश्यकता का हवाला देते हुए क्रिप्टो संपत्ति या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के संबंध में आपूर्ति की 'प्रकृति और कराधान' सहित कुछ मसलों को टालने का सुझाव दिया। वर्तमान में जीएसटी व्यवस्था के तहत क्रिप्टो संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। समिति ने एडिटिव्स के साथ फलों के गूदे, सोना, चांदी और हीरे तथा बैटरी स्टोरेज घटकों जैसी कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने की उद्योग की मांग ठुकरा दी है। एडिटिव के रूप में मिलाए गए कार्बन-डाईऑक्साइड वाले जूस पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा

एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान सात फीसदी पर अपरिवर्तित रखा

नयी दिल्ली। एजेंसी

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को सात फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है। हालांकि उसका अनुमान है कि एशिया की वृद्धि की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कमजोर रहने वाली है। एडीबी ने 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि सात फीसदी रहने का जो अनुमान जताया है वह सितंबर के अनुमान के समान ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि 2021-22 में देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि 8.7 फीसदी रही थी।

उसने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए भी जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7.2 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है। एडीबी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस वर्ष एशिया 4.2 फीसदी की दर से बढ़ेगा, 2023 में उसकी वृद्धि 4.6

फीसदी की दर से होने का अनुमान है। हालांकि पहले उसने इस वर्ष एशिया की वृद्धि दर 4.3 फीसदी और 2023 में 4.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। रिपोर्ट में कहा गया, ''वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 7 फीसदी की दर से वृद्धि करने का अनुमान है जिसकी वजह उसकी मजबूत घरेलू बुनियाद है।'' इसमें आगे कहा गया, ''उच्च आवृत्ति वाले कुछ हालिया संकेतक अनुमान से कहीं अधिक अनुकूल हैं मसलन उपभोक्ताओं का विश्वास, बिजली आपूर्ति, पीएमआई जबकि कुछ ऐसे संकेतक हैं जो पूरी तरह से अनुकूल नहीं हैं वे हैं निर्यात विशेषकर कपड़ा और लौह अयस्क का तथा उपभोक्ता उत्पादों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक।'' इसमें कहा गया कि 2023-24 के लिए 7.2 फीसदी के वृद्धि के अनुमान को बरकरार रखने की वजह संरचनात्मक सुधार और निजी निवेश को उत्प्रेरित करने वाले सार्वजनिक निवेश के सकारात्मक प्रभाव हैं।''एडीबी ने कहा, ''भारत में दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) के बीच अर्थव्यवस्था 6.3 फीसदी की दर से बढ़ी है, जो सार्वजनिक खपत में 4.4 फीसदी का संकुचन दर्शाता है। जबकि वैश्विक स्तर पर नरमी के बावजूद निर्यात 11.5 फीसदी की दर से बढ़ा।''

अमेरिका 2022-23 के लिए 64,716 अतिरिक्त एच2बी वीजा जारी करेगा

वॉशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका अस्थायी व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए अतिरिक्त 64,716 एच-2बी वीजा उपलब्ध करा रहा है। वीजा की यह श्रेणी अकुशल विदेशी कामगारों के लिए होती है। अमेरिका के इस कदम के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यहां की कंपनियां अपने व्यस्त सत्र के दौरान अपनी श्रम की जरूरतों के लिए योजना बना सकें।

एच-2बी वीजा के जरिये नियोक्ता गैर-कृषि या अन्य सेवाओं के लिए विदेशी कामगारों से सीमित अवधि के लिए अस्थायी तौर पर काम ले सकते हैं। हालांकि, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के इस कदम का विशेष असर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इस वीजा के लिए आवेदन देने वाले भारतीयों की संख्या ज्यादा नहीं है।

भारतीय आमतौर पर एच-2बी वीजा के लिए आवेदन नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका जाने वाले ज्यादातर भारतीय उच्च कौशल वाले पेशेवर होते हैं जिन्हें अमेरिकी कंपनियां ऐसी विशिष्ट भूमिकाओं जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिए रखती हैं। इस तरह के आव्रजन के लिए एच-1बी वीजा होता है। यूएससीआईएस ने एक बयान में कहा, ''गृह सुरक्षा विभाग और श्रम विभाग एक अस्थायी नियम जारी कर रहे हैं जिसके तहत वित्त वर्ष 2022-2023 में 64,716 अतिरिक्त एच-2बी अस्थायी गैर-कृषि कामकार वीजा उपलब्ध हो सकेंगे।'' ये अतिरिक्त वीजा उन अमेरिकी नियोक्ताओं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए जारी किए जा रहे हैं जिन्हें 15 सितंबर, 2023 से पहले अतिरिक्त कामगारों की जरूरत है।

पर्यावरण सहेजकर हम कई मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं: राष्ट्रपति

नयी दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि पर्यावरण सहेजकर हम कई मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि आने वाली पीढ़ी प्रदूषण मुक्त स्वच्छ हवा में सांस ले सके। मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेष पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किये। उन्होंने इस अवसर पर 'ईवी-यात्रा पोर्टल' भी पेश किया। इस पोर्टल को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने तैयार किया है। इसके जरिये निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर का पता लगाया जा सकेगा।

राष्ट्रपति ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ''यह सभी के लिये सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाली पीढ़ी प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण में सांस लें, अच्छी प्रगति करें और स्वस्थ जीवन जिए। स्वच्छ हवा में सांस लेना एक बुनियादी मानवाधिकार है।''

उन्होंने कहा, ''पर्यावरण की रक्षा कर, उसे सहेजकर हम कई मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं।'' मर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि की समस्या को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण वैश्विक के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि देश में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक औसत के एक-तिहाई से भी कम है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-26) में 'लाइफस्टाइल फॉर एनवॉयर्नमेंट' (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) यानी 'लाइफ' का संदेश दिया था। इसमें विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में हमारी जीवनशैली हमेशा 'लाइफ' के संदेश के अनुरूप रही है। मुर्मू ने कहा कि प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना और प्राकृतिक संपदा को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवनशैली का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा कि भारत पूरे वैश्विक समुदाय को ऐसी जीवनशैली अपनाने के लिये प्रेरित करने को प्रयास कर रहा है। भारत की जी-20 के लिये अध्यक्षता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जी-20 देश दुनिया के कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 85 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75 प्रतिशत का योगदान देते हैं। साथ ही दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी जी-20 देशों में रहती है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के अनुरूप 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का विचार दिया है और हम इसे विश्व पटल पर प्रसारित भी कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं, विशेषकर बच्चों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेष पुरस्कार के विजेताओं को उनकी नई सोच और कार्य के तरीके को भी सराहा। उन्होंने कहा कि उनके नवोन्मेष का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हो सकें और पर्यावरण संरक्षण के नये तरीके विकसित कर सकें। मुर्मू ने सभी से संकल्प लेने का आग्रह किया, ''हम जो कुछ भी करेंगे वह हमेशा प्रकृति के हित में होगा, प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं होगा।'' उन्होंने कहा कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में ही मानव कल्याण निहित है।

अगले पांच साल में भारत में 80 स्टार्टअप कंपनियों में आईपीओ लाने की क्षमता होगी : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में अगले पांच साल में 100 से अधिक परिपक्व, बड़े स्तर पर लाभ कमाने वाले या लाभ के रास्ते की ओर अग्रसर स्टार्टअप कंपनियां देखने को मिलेंगी। इनमें से 80 स्टार्टअप में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की क्षमता होगी। बाजार अनुसंधान और सलाहकार कंपनी रेडसीर की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स ने आईपीओ पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अबतक 20 स्टार्टअप कंपनियां आईपीओ ला चुकी हैं। रिपोर्ट कहती है, ''देश अगले पांच साल में 100 से अधिक परिपक्व, बड़े पैमाने पर लाभ कमाने वाले स्टार्टअप होंगे। उनमें से लगभग 20 पहले से ही सूचीबद्ध हैं। वहीं 80 अन्य में अपनी आईपीओ यात्रा शुरू करने की क्षमता होगी।'' एचएसबीसी के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी कंपनियां अब वृद्धि को प्राथमिकता दे रही हैं। अमेरिका में लगभग 43,000 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण में से लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा प्रौद्योगिकी या नई पीढ़ी कंपनियों का है। इनमें एप्पल और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 3,900 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण में प्रौद्योगिकी या नई पीढ़ी की कंपनियों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है।

सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वेदांता का 30 जापानी कंपनियों से करार

नयी दिल्ली। एजेंसी

वेदांता समूह ने मंगलवार को कहा कि उसने एक भारतीय सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए जापान की 30 प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ करार किए हैं। इन समझौतों पर जापान की राजधानी टोक्यो में पिछले सप्ताह आयोजित वेदांता-एवनस्ट्रेट बिजनेस पार्टनर्स समिट-2022 के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन में दुनियाभर की 100 कंपनियों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में कई वैश्विक कंपनियों ने भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण अभियान का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई।

वेदांता ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में एक सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण संयंत्र लगाने की घोषणा की हुई है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से इस संयंत्र को शुरू किया जाएगा। वेदांता ग्लोबल के प्रबंध निदेशक (डिस्प्ले एवं सेमीकंडक्टर व्यवसाय) आकर्ष के हेब्बर ने बयान में कहा कि उनकी कंपनी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेदांता सिर्फ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का एक परिवेश बनाने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहती है।

भारत 2030 तक 30 प्रतिशत भूमि और जल संरक्षित करने का लक्ष्य हासिल कर सकता है : सीओपी15 प्रतिनिधि

एजेंसी

मॉन्ट्रियल (कनाडा)। कनाडा में सीओपी15 जैव विविधता सम्मेलन में भारत की नुमाइंदगी कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत का करीब 27 फीसदी क्षेत्र संरक्षित है और वह 2030 तक 30 प्रतिशत भूमि और जल की रक्षा के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक (सीओपी15) चल रही है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सचिव जे. जस्टिन मोहन ने कहा कि भारत 113 देशों के 'हाई एम्बिशन कोलिशन' (एचएसी) का सदस्य है जिसका मकसद 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को 2030 तक संरक्षित करना है। इसे '30 गुणा 30' लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। मोहन ने कहा, ''संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, मैनग्रोव, रामसर स्थल, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र और सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र समेत भारत ने पहले ही करीब 27 फीसदी क्षेत्र संरक्षित कर लिया है।'' उन्होंने कहा, ''अब हम जैव विविधता धरोहर स्थल और अन्य प्रभावी संरक्षण उपायों (ओईसीएमएस) के जरिए और अधिक इलाकों को संरक्षण के तहत लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत 2030 में आसानी से '30 गुणा 30' का लक्ष्य हासिल कर सकता है।''

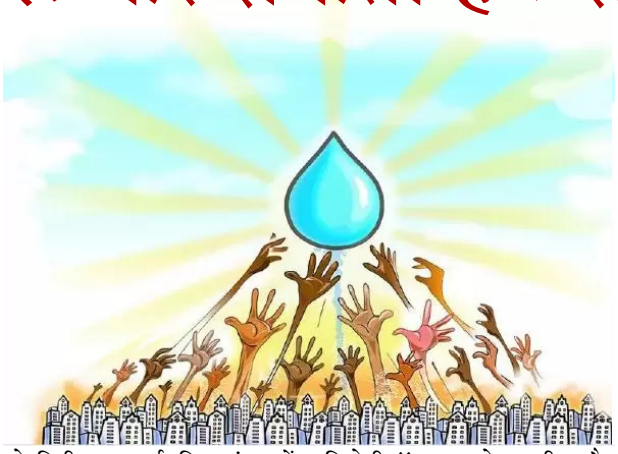

ओईसीएमएस वे इलाके होते हैं जो निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संरक्षित होते हैं। मोहन ने कहा, ''भारत में ओईसीएमएस के लिए असीम संभावना है और इससे अपने 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।'' भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के पूर्व अध्यक्ष विनोद माथुर ने कहा कि भारत ने ओईसीएमएस को परिभाषित करने के लिए 14 श्रेणी की वर्गीकरण प्रणाली बनायी है। माथुर ने कहा, ''इन्हें तीन व्यापक समूहों -क्षेत्रीय, जलाशयों और समुद्री इलाकों के तहत वर्गीकृत किया गया है।'' उन्होंने कहा कि हालांकि, इन ओईसीएमएस को संरक्षित करने के लिए स्थानीय समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है। मोहन ने कहा, ''भारत के पास सभी स्थानीय निकाय में स्थापित 2,77,123 जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं। हमारी वन्य पारिस्थितिकी के बाहर और इलाकों को जैवविविधता धरोहर स्थलों के तहत लाने की असीम संभावना है।'' उन्होंने कहा, ''ये इलाके औषधीय पौधों और पक्षी से समृद्ध हो सकते है। ये संरक्षित किए जाने पर इलाके में पारिस्थितिकी के प्रबंधन में मदद करेंगे और पर्यटन की संभावना बढ़ाएंगे, जिससे इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।'' संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के बारे में पूछे जाने पर मोहन ने कहा कि 2002 का जैविक विविधता कानून अन्य वन्य कानूनों के साथ सौहार्द्रपूर्ण तरीके से काम करता है जिससे स्वदेशी समुदायों की आजीविका में मदद मिलती है। 'वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड' (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) में शासन, कानून और नीति की निदेशक विशेष उप्पल ने कहा कि भारत जैसे देश में आदिवासी और स्थानीय समुदायों के प्रयासों को पहचानने तथा उनका समर्थन करना भी अहम है जो सामुदायिक संरक्षित इलाके बनाकर आर्द्र भूमि, वन और तटों का संरक्षण करते रहे हैं।

सूर्य के धनु में प्रवेश से शुरू होगा मलमास, मांगलिक कार्य पर लगेगा विराम

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद
अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

साल के आखिरी माह में सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे।जिसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि सूर्य के धनु राशि मे प्रवेश से मलमास का प्रारम्भ होगा जो कि 14 जनवरी मकर संक्रांति तक रहेगा। धनु संक्रांति आते ही अगले 30 दिन के लिए विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा। खरमास के समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय में सूर्य देव का प्रभाव कम होता है, इसलिए शुभ कार्य नहीं करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूरे एक वर्ष में दो बार ऐसा मौका आता है, जब मालमास लगता है। एक मालमास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच और दूसरा खरमास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक होता है।

क्यों बंद होते हैं शुभ कार्य

ज्योतिषियों की मानें तो गुरु देव बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं। सूर्य का बृहस्पति की राशि में प्रवेश इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा होने पर लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ जाता है. इस राशि में सूर्य के कमजोर होने कारण इसे मलमास कहते हैं।ऐसा कहा जाता है कि मलमास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है. सूर्य के कमजोर स्थिति में होने की वजह से इस महीने शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है।

मलमास में खर खींचते हैं सूर्य देव का रथ

पौराणिक कथा के अनुसार, मलमास के समय में सूर्य देव के भ्रमण की गति धीमी हो जाती है। सूर्य देव के रथ के घोड़े आराम करते हैं और उनके रथ को खर खींचते हैं। इस बदलाव की वजह से इस माह को मलमास कहा जाता है।

खरमास या मलमास में नहीं करने चाहिए ये काम

- खरमास में शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस समय अगर विवाह किया जाए तो भावनात्मक और शारीरिक सुख दोनों नहीं मिलते हैं।

- इस समय मकान का निर्माण या संपत्ति की खरीदारी वर्जित होती है। इस दौरान बनाए गए मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता है।

- खरमास में नया कार्य या व्यापार शुरू न करें। इससे व्यापार में शुभ फलों के प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

- इस दौरान द्विरागमन, कर्णवेध और मुंडन जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं, क्योंकि इस अवधि के किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की सम्भावना होती है।

श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के क्या हैं फायदे और कैसे करें इसका जाप

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में हमेशा भक्तों से भगवान शिव को जल अर्पित करने के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने को कहते हैं। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र शिव पुराण का मंत्र है, इसे महामृत्युंजय मंत्र के समान ही प्रभावशाली माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का अर्थ है कि भगवान श्री शिव को मैं नमस्कार करता हूं। यह भी माना जाता है कि सिर्फ एक बार इस मंत्र का जाप करने से एक हजार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का फल मिलता है।

श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के फायदे

पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में कई बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के फायदे बता चुके हैं। भगवान शिव का यह मंत्री बहुत प्रभावशाली बताया गया है। जीवन में सुख-शांति, धन, समृद्धि इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के जाप से मिलती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली सारी बाधाएं हट जाती हैं। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप उस कार्य में सफलता प्रदान करने वाला बताया गया है। बीमारी और किसी भी प्रकार के रोग के दौरान इस मंत्र का जप करना भी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक बताया गया है।

इस तरह करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप

भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जाप हमेशा स्नान के बाद, भगवान के सामने बैठकर शुद्ध मन से करना चाहिए। मंत्र के जाप के दौरान आप ऊन या कुशा का आसान उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करें तो यह और भी फलदायी होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्ममुहूर्त और प्रदोषकाल के समय इसका जाप करना सबसे उत्तम समय माना जाता है। सोमवार और प्रदोष के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए रुद्राक्ष माला से 108 बार इस मंत्र के जाप से एक लाख आठ हजार बार महातमृत्युंजय मंत्र के जाप का फल मिलता है।

अशोक के पत्ते से करें ये 4 उपाय, बदल जाएगा भाग्य, होगा धनलाभ

अशोक के पत्तों का उपयोग धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए प्राचीन समय से होता आ रहा है। अशोक के पत्ते बेहद शुभ माने जाते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर अशोक या आम के पत्तों से बनी माला अवश्य लटकाई जाती है। ऐसा करने के पीछे कई ज्योतिषीय कारण बताए जाते हैं। इसके पत्ते पूजा के कलश में भी रखे जाते हैं। ज्योतिष में अशोक के पत्तों के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से पीछा छुड़ा सकते हैं। जानिए ऐसे ही उपायों के बारे में

धन वृद्धि के उपाय

धार्मिक स्थल पर लगे अशोक के पेड़ की जड़ को शुभ मुहूर्त में अपने घर ले लाएं। जड़ को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो लीजिए फिर सुखाकर धन की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी।

घर से दूर होगी नकारात्मकता

घर के मुख्य द्वार और सभी कमरों के दरवाजे पर अशोक के पत्तों की माला सजाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है। पत्ते सूखने पर माला बदल लें। यह उपाय 7 बार करें।

घर के झगड़े व क्लेश से मिलेगी मुक्ति

यदि आपके घर में बार-बार लड़ाई झगड़े या किसी भी प्रकार का क्लेश होता है तो घर में मुखिया को अपनी पत्नी सहित प्रतिदिन अशोक के पेड़ में पानी सींचना चाहिए। इससे मां आदिशक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस उपाय को करने से घर में शांति बनी रहती है।

विवाह के लिए उपाय

ऐसे अविवाहित लोग जिनका लगातार प्रयासों के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें नहाने के पानी में अशोक के पत्ते डालना चाहिए और स्नान के बाद इन पत्तों को निकाल कर किसी पीपल के पेड़ के पास साफ-सुथरे स्थान पर रख दें। बहुत जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी।

आचार्य संतोष भार्गव
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

घर में आजमाएं ये तीन टिप्स, नए साल में बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

आने वाले नए साल में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत और सुदृढ़ हो, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। इसके लिए वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिनके आजमाने से धन की कमी नही रहेगी। साल के आखिरी माह दिसंबर में घर में ये तीन टिप्स को आजमाएंगे तो साल 2023 खुशहाली ही बीतेगा।

पानी की टंकी का रंग और दिशा का सही होना

वास्तु शास्त्र में घर में पानी की टंकी की दिशा सदैव उत्तर-पूर्व होना चाहिए। गलत दिशा में रखने से घर में दरिद्रता का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में आर्थिक और शारीरिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालती है। इस तरह के वास्तु दोष को कम करने के लिए पानी की टंकी को सफेद रंग के कलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

दिशानुसार रखे घर की अलमारी

घर की सबसे महत्वपूर्ण चीज अलमारी होती है, जिसकी दिशा गलत होने से कंगाली जैसी स्थिति भी हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलमारी को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अलमारी को उत्तर-पूर्व की दिशा में नही रखना चाहिए क्योंकि ऐसे में दरवाजे दक्षिण दिशा में खुलने से घर में मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं।

एक्वेरियम का होना घर की सुख-समृद्धि बढाना

एक्वेरियम घर की सुंदरता बढाने के साथ- साथ समृद्धि का भी प्रतीक है। सुंदर रंग-बिरंगी मछलियां को देखकर मानसिक सुख का अनुभव भी कराती हैं । सुनहरे रंग की मछली हमेशा शुभ मानी जाती है। एक्वेरियम को घर में हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसमें हमेशा 9 मछलियां होनी चाहिए। समय-समय पर इसका पानी भी बदलना पडता है ,नही तो घर की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है । इसे बेडरूम और रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए ।

इस साल नवंबर में पिछले साल के मुकाबले 3 लाख 22 कारें ज्यादा बिकीं

हर माह प्रदेश में बिक रही है 14 हजार कारें इनमें से 6500 मारुति की, नवंबर में हर 10 में से 7 सेल मारुति सुजुकी की है

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना के बाद से सेमीकंडक्टर की कमी से परेशान ऑटोमोबाइल अब धीरे-धीरे वापसी करने के लिए तैयार है। इस वर्ष नवंबर के लिए इंडस्ट्री वॉल्यूमः पिछले साल के मुकाबले 31.5 प्रतिशत, यानी 3,22,000 यूनिट्स ज्यादा रहा। अभी तक किसी भी वित्त वर्ष में नवंबर के लिए यह सबसे बड़ी संख्या। पिछले 06 माह में उद्योग ने 300,000 यूनिट्स का वॉल्यूम पार कर लिया। पिछले 11 महीने में उद्योग ने 2,93,000 यूनिट्स का वॉल्यूम पार कर लिया। बहुत अच्छी वापसी प्रतीत हो रही है।

इंडस्ट्री के लिए इस कैलेंडर वर्ष में 38 लाख यूनिटों का अनुमान है। इससे पहले सर्वाधिक वॉल्यूम कैलेंडर वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था, जो 33.8 लाख यूनिट का था। सेमीकंडक्टर की स्थिति में सुधार हो रहा है। नवंबर में हर 10 में से 7 सेल मारुति सुजुकी की है। इंडस्ट्री के सर्वोच्च पाँच मॉडल छोटी कारों के हैं। उद्योग में बैकलॉग लंबित बुकिंग 7.5 लाख यूनिट की है। नए मॉडलों में सीएनजी का विस्तार किया जा रहा हैः स्विफ्ट में 12 से 13 प्रतिशत और एक्सएल6 में 16 से 17 प्रतिशत। मारुति सुजुकी के लिए अकेले सीएनजी की लंबित बुकिंग 107,000 हैं। उद्योग में 246,000 यूनिट्स (22 दिनों) का अनुमानित स्टॉक है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि मप्र. के ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। यहां हर माह 14 हजार पैसेंजर व्हीकल की सेल होती है। इनमें से करिब 6500 मारुती है यानी मारुति का मार्केट शेयर 46इ। पिछले साल की तुलना में 45इ ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है। प्रदेश में बिकने वाली सभी सेल का 40 प्रतिशत हिस्सा इंदौर से आता है। वहीं भोपाल में 18 प्रतिशत है। इंदौर में हमारा मार्केट शेयर 49 प्रतिशत है।

नई BMW M340i x ड्राइव भारत में लॉन्च

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में सबसे लोकप्रिय एम इंजीनियर्ड कार है, जो अब तरोताजगी से भरपूर नए डिजाइन और ज्यादा रोमांचक डायनैमिक्स के साथ पेश की गई है। स्थानीय स्तर पर बनाई गई सबसे तेज BMW M340i ॅ सेकेंड में 0-100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है सफर पर जाने के लिए हमेशा तैयार 6 सिलिंडर 'एम पेट्रोल इंजन के साथ एम पावर बीएमडब्ल्यू इंडिया ने देश में आज नई BMW M340i ॅ ड्राइव लॉन्च की। यह कार बीएमडब्लू के चेन्नई स्थित ग्रुप प्लांट में स्थानीय रूप से बनाई गई है। यह कार बुकिंग के लिए बीएमडब्लू डीलरशिप नेटवर्क के पास उपलब्ध है। इसे आनला?न भी इसकी बुकिंग कराई जा सकती है। इस कार की डिलिवरीज जनवरी 2023 से शुरू होगी। 2021 में भारतीय बाजार के लिए खासतौर पर बनाई गई, BMW M340i x एक हाईपरफॉर्मेंस वाली बीएमडब्लू है, जिसे एम इंजन के साथ भारत में बनाया गया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार डिजाइन, नए-नए फीचर्स के साथ अपनी श्रेणी में अनोखे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के चलते यह मॉडल अपने सेग्मेंट में सबसे बेस्ट बनकर भरा है। बीएमडब्लू ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट श्री विक्रम पावा ने कहा, 'BMW M340i x ड्राइव निश्चित तौर पर विजेता है क्योंकि यह ड्राइविंग की खुशी और जुनून को एक अलग स्तर तक ले जाती है। इसका क्रेडिट ड की पावर को देना चाहिए, जिसे कार के दायीं ओर अंकित किया गया है। यह आकर्षक फॉर्म्युला उन कारों के शौकीनों की इच्छा को शांत करने करने के लिए बनाया गया है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए प्रीमियम सेडान चाहते हैं, जिससे जब इच्छा हो तो इस मशीन की परफॉर्मेंस को दोगुना किया जा सके। आज यह ठडॅ ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक है। नई ठडॅड 340प ग ड्राइव ड परफॉर्मेंस, कभी न हारने और थकने वाली गतिशीलता. जगह, सुरक्षा और नए-नए फीचर्स का अनोखा पैकेज पेश करती है। कार का ताजगी से भरपूर नया अवतार ड340प की नंबर वन पोजिशन को और मजबूत बनाएगा। इससे ब्रैंड के फैंस और इस श्रेणी की ड कारों के प्रति खासा जुनून रखने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी।

नई BMW S 1000 RR अब भारत में लांच

बेहतर परफॉर्मेंसरू 210 हॉर्स पावर की रेसट्रैक तत्परताए सर्वश्रेष्ठ डाइनेमिक्स

बीएमडब्लू मोटोराड की बेहद मशहूर सुपर स्पोर्ट बाइक का एकदम नया संस्करण BMW S 1000 RR भारत में लॉन्च किया गया। कंपलीटली बिल्टअप यूनिट के तौर पर लॉन्च की गई बाइक बीएमडब्लू मोटोराड के डीलर नेटवर्क पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। बाइक की डिलिवरी की शुरुआत फरवरी 2023 से होगी। प्रतिस्पर्धी श्रेणी में आरआर एक मानक है और उन रेसिंग उत्साहियों के बीच बेहद लोकप्रिय है जो स्पीड के दीवाने है। 2009 में यह बाइक पहली बार लॉन्च की गई थी। हर जेनरेशन ने इस खेल के नियमों को फिर से परिभाषा दी है। यह परंपरा नए आआ के साथ बरकरार है। नई BMW S 1000 RR अपने व्यापक आधुनिकरण के दम पर पिछले संस्करणों से काफी बेहतर है। इसके लिए गाड़ी के इंजन, सस्पेंशन, चेसिस, एरोडायनेमिक्स, डिजाइन और असिस्टेंस सिस्टम को श्रेय दिया जाना चाहिए। बाइक निर्माण के कई क्षेत्रों में इंजीनियरिंग में सुधार किए गए हैं। इसके नतीजे के तौर पर यह शानदार बाइक पहले से और बेहतर बन गई है।

बीएमडब्लू ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट श्री विक्रम पावाह ने लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए कहा किए BMW S 1000 RR मोटोराड रेसिंग डीएनए का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। रेसट्रैक या रोड पर त् का मतलब है कभी भी दूसरी पोजीशन पर नहीं रहना हमेशा सबसे आगे रहना । आरआर राइडर्स इसकी जोश.जुनून से भरी परफॉर्मेंस को बेहद पसंद करते हैं। वह अपनी सीमा से बाहर जाकर प्रदर्शन करते हैं। यह बाइक इंजन की ज्यादा पावर और शार्पर डिजाइनए शानदार एरोडायनेमिक्स और हैंडलिंग डायनेमिक्स के नए.नए फीचर्स से लैस है। नई w 1000 RR हमेशा आपके साथ किसी भी सफर पर जाने के लिए तैयार रहती है। यह निर्विवाद रूप से अपनी क्लास में विजेता के तौर पर इस बाइक की विश्वसनीय स्थिति की फिर से पुष्टि करती है। यह राइडर्स को हमेशा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करती है।

स्मार्टर लॉजिस्टिक्स ने एक नई अखिल भारतीय ग्राउंड एक्सप्रेस सर्विस - 'व्हीलेक्स' के शुभारंभ की घोषणा की

पिछले 12 महीनों में अखिल भारतीय एयर एक्सप्रेस सर्विस को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद, स्मार्टर ने देश भर में एक मजबूत लाइन हॉल वेहिक्यूलर नेटवर्क और 10 नए ट्रांजिट हब के माध्यम से डोर-टू-डोर ग्राउंड एक्सप्रेस सर्विस को शामिल करने के लिए अपनी पेशकश का विस्तार किया।

मुंबई/नई दिल्ली। स्मार्टर लॉजिस्टिक्स ने अपने मौजूदा एयर एक्सप्रेस (एरेक्स) उत्पादों के अलावा एक अनूठी ग्राउंड एक्सप्रेस सेवा - 'व्हीलेक्स' पेश की है, जो डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान करती है। श्री योगेश धींगरा, संस्थापक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्टर लॉजिस्टिक्स कहते हैं , 'भारत के लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए सरकार की महत्वाकांक्षा के अनुरूप, स्मार्टर ने सस्ती दरों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सर्विस प्रदान करने के लिए व्हीलेक्स की शुरुआत की। सितंबर 2022 में सरकार द्वारा घोषित नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स सर्विसओं को सुव्यवस्थित और डिजिटाइज़ करना है और स्मार्टर कुशल, तेज और समय पर डिलीवरी के लिए इष्टतम तकनीक का उपयोग करके लॉजिस्टिक्स की समग्र लागत को कम करने के लिए बाजार की मांगों को संबोधित कर रहा है।स्मार्टर ने व्हीलेक्स को चार अलग-अलग एक्सप्रेस सर्विसओं में अनुकूलित किया है - व्हीलेक्स कार्गो (बी2बी), व्हीलेक्स शेयर (पार्ट ट्रक लोड), व्हीलेक्स जंबो (पूर्ण ट्रक लोड), और व्हीलेक्स ईकॉम। यह अनूठी सर्विस गारमेंट्स, रिटेल, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, होम अप्लायंसेज, ऑफिस सप्लाई आदि जैसे सभी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं की विविध रेंज को पूरा करती है। बी2बी जरूरतों को पूरा करने वाले दिन-निश्चित डिलीवरी शेड्यूल के साथ डोर-टू-डोर एक्सप्रेस कार्गो आवाजाही के लिए, ग्राहक व्हीलेक्स कार्गो का विकल्प चुन सकते हैं। स्मार्टर का व्हीलेक्स शेयर पार्ट-ट्रक लोड समाधान के माध्यम से पैसे के लिए मूल्य की पेशकश करने वाले सामानों की शिपिंग के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है। इसी तरह, शिपर्स व्हीलेक्स जंबो के माध्यम से लंबी दूरी पर थोक वस्तुओं और भारी भार को ढो सकते हैं, जो पॉइंट-टू-पॉइंट ग्राहक समर्पित पूर्ण ट्रक लोड सर्विस प्रदान करते हैं। भारत में ईकामर्स की घातीय वृद्धि के साथ, स्मार्टर ने एक विशिष्ट सर्विस भी बनाई है - व्हीलेक्स ईकॉम, विशेष रूप से भारत की ई-कॉमर्स और डी2सी कंपनियों के लिए, प्रीपेड और सीओडी (नकद/डिजिटल भुगतान) दोनों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की पूर्ति की पेशकश प्रत्यक्ष सतह लाइन हॉल कनेक्टिविटी के माध्यम से मूल से गंतव्य तक फैली हुई है जिससे आर्थिक रूप से तेजी से वितरण के लिए अग्रणी है।

'श्री सार्थक धींगरा, वीपी - इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन और क्वालिटी के प्रमुख, स्मार्टर लॉजिस्टिक्स कहते हैं, 'व्हीलेक्स के संचालन का समर्थन करने के लिए, स्मार्टर ने दिल्ली / एनसीआर, मुंबई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में देश भर में 10 ट्रांजिट हब जोड़े हैं। ये 86इ शहरों और 133 से अधिक स्मार्ट सर्विस केंद्रों के हमारे मौजूदा अखिल भारतीय कवरेज के अतिरिक्त हैं। अगले तीन महीनों के भीतर, स्मार्टर देश के भीतर प्रमुख मार्गों के साथ कुल 20 ट्रांजिट हब के साथ-साथ कुल 100इ शहरों के लिए अन्य 15 नए शहरों में 10 और ट्रांजिट हब जोड़ देगा। '

इसके अलावा, श्री रवि पटेल, मुख्य रणनीति अधिकारी, परियोजनाओं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख ने कहा, 'स्मार्टर नए जमाने के ग्राहकों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील लॉजिस्टिक सर्विस है। नई व्हीलेक्स सर्विस भारत में लॉन्च से ही प्रत्येक शिपमेंट की 24/7 रीयल-टाइम पीस-लेवल ट्रैकिंग प्रदान करने वाली कुछ सर्विसओं में से एक होगी। व्हीलेक्स में अद्वितीय सुरक्षा विशेषताएं शामिल होंगी जैसे कि सभी लाइन हॉल वाहनों पर डिजिटलीकृत ताले जिन्हें केवल गंतव्य स्थान पर ओटीपी के साथ खोला जा सकता है। किसी भी वातावरण में शिपमेंट की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कंटेनरीकृत वाहन, कार्गो नेट और विभाजक जैसी अतिरिक्त सावधानियों का उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, व्हीलेक्स केंद्रों को अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी द्वारा 24/7 कवर किया जाएगा।

बीरा 91 ने राइज़ लॉन्च करने की घोषणा की

इंदौर। एजेंसी

दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही बीयर कंपनी बीरा 91 ने देश की पहली प्रीमियम राइस स्ट्रॉन्ग लागर राइज़ लॉन्च करने की घोषणा की है बीरा 91 राइज़ दरअसल एशियाई परंपराओं के मुताबिक पेश प्रीमियम राइज़ लागर है। जिसे भारत में उपलब्ध स्थानीय चावल से तैयार किया जाता है और यह ड्राइ, लाइट तथा ब्रिलिएंट स्पार्कल के साथ आती है। 8ः एबीवी से भी कम के साथ पेश लागर प्यास बुझाने वाली है जिसमें जापान की सोराची एस हॉप्स से ताज़गी का अद्भुत अहसास मिलता है और यही इस बीयर को इसका खास लैमन सिट्रस एरोमा भी देती है। राइज़ बीयर नए दौर के उन आधुनिक ग्राहकों के लिए है जिन्हें अलग फ्लेवर्स की तलाश है और यह बीरा 91 के पहले से मौजूद सात खास फ्लेवर्स वाले पोर्टफोलियो में एक नई पेशकश है।

राइज़ के लॉन्च के बारे में अंकुर जैन फाउंडर एवं सीईओ बीरा 91 ने कहा भारत में चावल को काफी पसंद किया जाता है और राइज़ तैयार करने के लिए हमने देश के तटीय इलाकों से प्राप्त चावलों का इस्तेमाल किया है जबकि इसमें मिली सोराची एस हॉप्स को जापान से मंगवाया जाता है। हमारी ब्रुइंग टीम ऐसे फ्लेवर्स बनाने के लिए खासतौर से काम करती है जिनका लोकल कनेक्ट हो और जिनसे ग्राहकों को कोई खास अनुभव मिले। हम भारत की पहली स्ट्रॉन्ग लागर लॉन्च कर रोमांचित हैं और हमें पूरा भरोसा है कि राइज़ देश की प्रीमियम स्ट्रॉन्ग लागर कैटेगरी में गेम-चेन्जर साबित होगी।लाइट बॉडी, क्लीन और क्रिस्प टैक्सचर के साथ, राइज़ वाकई खास है। इसका राइस बेस (चावल) इसे ड्राइ और लाइट बनाता है जबकि सोराची एस हॉप्स से इसमें समाता है इसका मोहक सिट्रस एरोमा। राइज़ को करी, स्पाइसी डिश या बारबेक्यू के साथ लिया जा सकता है और यह पैलेट-क्लींज़र की तरह भी है। बीरा 91 राइज़ को देशभर के महानगरों में 330 मिली तथा 650 मिली की बोतलों और 500 मिली कैन्स में उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत में रियलमी 10 प्रो सीरीज़ का अनावरण हुआ

नंबर सीरीज़ में यूज़र्स के लिए सर्वश्रेष्ठ आधुनिक विशेषताएं

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

5जी इनेबल्ड स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले भारत के पहले ब्रांड और सबसे भरोसेमंद टेक ब्रांड, रियलमी ने अपने लेटेस्ट यूथ फ्लैगशिप स्मार्टफोंस - रियलमी 10 प्रोः 5जी और रियलमी 10 प्रो 5जी के लॉन्च की घोषणा की। रियलमी 10 प्रो सीरीज़ 5जी को उत्कृश्टता के साथ बनाया गया है। इसमें अद्भुत डिस्प्ले, फ्लैगशिप कैमरा, शक्तिषाली 5जी प्रोसेसर है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदान करता है। इसमें बॉक्स में रियलमी यूआई 4.0 मिलता है। अपनी नंबर सीरीज़ में नए उत्पाद के साथ रियलमी एक बार फिर यूज़र्स को ज्यादा आधुनिक व संपूर्ण अनुभव प्रदान कर रहा है, और मिड से लेकर हाई एंड सेगमेंट में अपनी पहुँच का विस्तार कर रहा है।

लॉन्च के बारे में माधव शेठ, सीईओ, रियलमी इंडिया, वीपी, रियलमी, और प्रेसिडेंट, रियलमी इंटरनेशनल बिज़नेस ग्रुप ने कहा, ''रियलमी नंबर सीरीज़ भारत और विश्व में हमारे यूज़र्स द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की गई सीरीज़ है। यूज़र्स को ज्यादा आधुनिक टेक्नॉलॉजी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ हमने हमेषा नंबर सीरीज़ के हर उत्पाद में ज्यादा आधुनिक विषेशताएं प्रदान की हैं, जो अपने मूल्य वर्ग में सर्वश्रेश्ठ हैं। रियलमी 10 प्रो सीरीज़ 5जी के साथ हमारा उद्देष्य नंबर सीरीज़ में बाजार की सर्वोत्तम विशेषताएं पेश करना और यूज़र्स को प्रीमियम फीचर्स प्रदान करना है। इन दोनों स्मार्टफोंस में फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले और 'शक्तिशली 5जी प्रोसेसर है, जो भारत में 5जी को जनसमूह तक पहुँचाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुश्टि करता है।

इंटरफ्लोरा इंडिया ने शानदार फ्लोरल डेकॉर के क्षेत्र में पहली बार इंदौर में प्रवेश किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंटरफ्लोरा इंडियाः द फ्लावर एक्सपर्ट्स को आंत्रप्रेन्योर अनुजा जोशी द्वारा भारत में अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। अनुजा के नेतृत्व में, आज इंटरफ्लोरा इंडिया ने क्षेत्र में बहुत कम समय में अपना अहम् स्थान बना लिया है, जो देश में विश्व स्तर के फ्लोरल एक्सपीरियंसेस, स्टेटमेंट गिफ्ट्स और शानदार सजावट देने का पर्याय बन चुका है। विगत पाँच वर्षों में, इंटरफ्लोरा ने भारत में कुछ सबसे बड़ी शादियों और इवेंट्स के लिए फ्लोरल डेकॉर का जिम्मा बखूबी उठाया है। इन शादियों और इवेंट्स की सूची में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, कुणाल रावल और अर्पिता मेहता, ऋचा चड्ढा और अली फज़ल, गोयनका और अंबानी परिवार, सोनम बबानी, द हाउस ऑफ मीसु के नाम शामिल हैं।

इंटरफ्लोरा इंडिया, फ्लोरल ब्यूटी के क्षेत्र में अपनी शानदार सजावट की प्रतिबद्धता के साथ इंदौर शहर में पहली बार अपने आगमन का जश्न मना रहा है, जो कि ट्रेज़र आइलैंड मॉल में 9 दिसंबर से 18 दिसंबर, 2022 तक चलेगा।

अनुजा जोशी, को-फाउंडर और सीईओ, इंटरफ्लोरा इंडिया, कहती हैं, 'इंटरफ्लोरा इंडिया की हर एक डिज़ाइन में फूलों की सुंदरता निहित है। हमारी तमाम डिज़ाइन्स फूलों की खुशबू और खूबसूरती के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इंटरफ्लोरा इंडिया में, सजावट को लेकर हमारी कोशिश यही रहती है कि यह इवेंट को जीवंत रूप देने के साथ उससे संबंधित व्यक्ति को बेशकीमती यादें दे जाए, जिसे वह आजीवन संजोकर रखे, साथ ही इसमें शामिल हर एक व्यक्ति को शांति और सौम्यता की शानदार छवि पेश कर जाए।' ब्रांड को एक इमर्सिव पॉप अप जोन के माध्यम से इंदौर शहर में हैंडक्राफ्टेड फ्लोरल एक्सपीरियंसेस की पेशकश करने पर गर्व है। इसका इंटरैक्टिव डिस्प्ले अद्भुत लैवेंडर फूलों से सुसज्जित किया गया है। वहीं बैकड्रॉप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह दर्शकों की वीरल फूलों को देखने की तमन्ना को पूरा करेगा, जो आमतौर पर दुर्लभ स्थानों पर ही मिलते हैं। चिराग डेंगरा, क्रिएटिव डायरेक्टर, इंटरफ्लोरा इंडिया, कहते हैं, 'हम इंदौर के दर्शकों के लिए इंटरफ्लोरा लाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अत?यंत सुंदर और प्रीतिकर फूलों से खूबसूरत फ्लोरल अरेंजमेंट, हैम्पर्स और बीस्पोक डेकॉर सॉल्यूशंस के लिए बेहद सतर्कता के साथ तैयार किए जाते हैं। इंटरफ्लोरा इंडिया, इंदौर में हर अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राहक को कभी न बदलने वाली यादें दे जाता है।'

भारत के लिए नियम तोड़ देगा रूस?

एजेंसी।

मिनिमम रेट की शर्त भी हटने से और सस्ता मिलेगा कच्चा तेलनई दिल्लीः सस्ते पेट्रोल-डीजल का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। खुशखबरी रूस से रास्ते से आ सकती है। दरअसल रूस से और सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिलने के आसार दिख रहे हैं। भारतीय रिफाइनरियों को रूस से कम कीमतों पर कच्चा तेल मिल सकता है। रूस भारत को 60 डॉलर प्रति बैरक से भी कम पर क्रूड ऑयल बेच सकता है। भारत अपनी जरूरत के मुताबिक रूस से तेल खरीदता रहा है। यूरोपीय संघ ने रूसी तेल की कीमत पर 60 डॉलर प्रति बैरक की कैपिंग लगाई है, लेकिन भारत इस कैपिंग का समर्थन नहीं करता है। दरअसल तेल की कीमतों पर कैपिंग कर पश्चिमी देश तेल की वैश्विक कीमतों और आपूर्ति को स्थिर बनाये रखने के साथ-साथ रूस के तेल राजस्व को कम करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से 60 डॉलर प्रति बैरक से कम कीमत पर खरीद सकता है। अगर भारत को सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है तो इसका लाभ आपको भी मिलेगा। पेट्रोल-

डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

बाजार के हिसाब से तय हो रेट

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद भारतीय रिफाइनरियों को रूस से और सस्ती दर पर कच्चा तेल मिल सकता है। भारत हमेशा से इस बात का समर्थन करता रहा है कि कच्चे तम की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के हिसाब से तय होनी चाहिए, न कि किसी देश या देशों के समूहों के मुताबिक। रूस बाजार की अवहेलना नहीं कर सकता है और न ही कैप से अधिक दरों पर बेचने के लिए डिस्काउंट को कम कर सकता है। रूस पर लगे प्रतिबंधों को लेकर रत्नागिरी रिफाइनरी एंड प्रेट्रोकैमिकल के सीईओ एमके सुरैना ने कहा कि प्राइस कैप के जरिए कई देश चाहते हैं कि रूस का तेल बाजार में न आ सके।

60 डॉलर प्रति बैरक से कम पर मिल सकता है कच्चा तेल

भारत रूस समेत ईरान और वेनेजुएला समेत अन्य देशों से भी कच्चा तेल खरीदता है। अब जितना जरूरी भारतीय कंपनियों के लिए रूस से मिलने वाला कच्चा तेल है उतना ही जरूरी रूसी तेल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार भी है। दरअसल अमेरिका समेत यूरोपीय संघ ने रूस पर तेल की कीमतों पर 60 डॉलर प्रति बैरक की सीमा तय की है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। पिछले दिनों क्रूड ऑयल 11 महीनों से निचले स्तर पर पहुंच गया।

रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

भारत के लिए रूस हमेशा से तेल का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। नवबंर महीने में जारी आंकड़ों के मुताबिक लगातार दूसरे महीने रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता रहा है। वॉर्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अपने इराक और सऊदी अरब के मुकाबले रूस से अधिक तेल खरीदे। 31 मार्च 2022 तक भारत से तेल आयात में रूस से खरीदे गए तेल का हिस्सा मात्र 0.2 फीसदी था, जो अब बढ़कर 20 फीसदी तक पहुंच गया है। सिर्फ नवंबर में भारत ने रूस से 9,09,403 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा है। इस दौरान इराक से 8,61,461 बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब से 5,70,922 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा है। अगर एक साल के आंकड़ों पर दौर करें तो दिसंबर 2021 में रूस से भारत मात्र 36,255 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल आयात करता था, जो मार्च 2022 तक ये 68,600 बैरक प्रतिदिन पर पहुंच गया। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, जिसके बाद भारत और रूस के बीच कच्चे तेल का आयात बढ़ा। नवंबर में यूरल क्रूड ऑयल जो भारत-रूस तेल आयात का 80ः था, लगभग 49 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि ईएसपीओ ब्लेंड और सोकोल क्रमशः 62 डॉलर और 69 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।